(iv) Effluent chemicals are treated in the treatment plants before these are discharged out of the power plant areas.

(v) In case of gas fired gas turbine power plants, methods like streak injection etc. are applied to keep the NOX levels within limits.

(vi) Nitrous gases (NOX) emissions are controlled by providing modern design of coal burners. New technologies like Fluidised Bed Combustion are also being tried for application on smaller plants.

Pending Proposals for Gas-Based Power Projects in Madhya Pradesh

4534. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether a number of gas-based power projects, intended to be fed from HBJ pipeline, submitted by Madhya Pradesh Government have been pending with Government ;

(b) if so, what are details thereof and what is their present status ; and

(c) whether the projects have been cleared from various technical angles, including the environmental aspect, if so, the details in this regard, and if not, the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) to (c) In view of the constraints in the availability of gas, no gas-based power plant is being considered to be set-up in the State of Madhya Pradesh.

The requisite details of gas-based power projects intended to be fed from the HBJ pipeline submitted by the Madhya Pradesh Electricity Board which have since been returned to them are given in the Statement.

Statement

Sl. No.	Name of the Project and capacity	Estimated Cost (Rs. Crores)	Date of return	Status
1	2	3	4	5
1.	Vijaypur Combined Cycle Gas Turbine Project (2×30 MW GT + 1×30 MW ST)	11,700	10/91	Clearance not tied include; associated transmission system clearance of environmental agencies (centre).
2.	Gwalior Combined Cycl/Gas Turbine Project (817 MW)	838	9/92	Clearances/inputs not tied up include; gas linkage, associated transmission system etc.

विद्युत संचालित जल-पम्पों के लिए बिजली के कनेक्शन

4535. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई के प्रयोजनार्थ जल-पम्पों के लिए बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने हेतु किसानों की प्रतीक्षा-सूची में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सूची का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा और विलम्ब किए बिना सिंचाई पम्पों के लिए बिजली के कनेक्शन देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैय्या नायडू) : (क) उपलब्ध सूचनानुसार, जिन किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, अधिकतर राज्यों में उनकी प्रतीक्षा-सूची की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(ख) 1991-92 एवं 1993 में मार्च के अन्त तक पम्पसेट कनेक्शनों की लम्बित सूची का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है (**नीचे देखीए**) ।

(ग) प्रत्येक वर्ष कितने पम्पसेटों को उर्जीकृत किया जाना है । इसका निर्णय योजना आयोग के अनुमोदन से संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है । पम्पसेट उर्जीकरण कार्यक्रमों को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से ग्रामीण

विद्युतिकरण निगम (आई० ई० सी०) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है । चालू वर्ष की वार्षिक योजना में पूरे देश में 2,86,119 पम्प सेटों के उर्जीकरण की परिकल्पना की गई है ।

विवरण

सिंचाई पम्प सेटों के लिए लम्बित आवेदनों की संख्या

क्र० सं०	राज्य	31-3-91	31-3-92	31-3-93
1.	आन्ध्र प्रदेश	282632	297739	318978
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	6502	8525	9100
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	195104	225432	239677
7.	हरियाणा	59531	57395	62936
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक	47992	46079	43898
11.	केरल	10913	11932	6462
12.	मध्य प्रदेश	24602	49027	45455
13.	महाराष्ट्र	328750	298515	312544
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	5367	3235	4782
19.	पंजाब	261924	269096	297980
20.	राजस्थान	202251	212483	225300
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	485415	491218	492720
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	24204	26306	29676
25.	पश्चिम बंगाल	24431	26150	27761

Availability of Funds SEBs

4536. DR. NAUNIHAL SINGH : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that once the Power Finance Corporation has made a scrutiny, all the financial institutions have to make available funds to State Electricity Boards without further scrutiny ;

(b) if so, whether it is being followed by the financial institutions ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.